दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ के उन संकल्पों में विलम्ब होने पर चिन्ता व्यक्त की जिनमें हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई है ;

(ख) जी हां। द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर विशेष बल दिया गया। भारत ने मालदीव को उसके विकास कार्यों में मदद देने की पेशकश की बातचीत में भारत-मालदीव व्यापार और जहाजरानी मत्स्य उद्योग में सहयोग और मालदीव में ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए भारतीय सहायता के संबंध में भी चर्चा हुई।

(ग) जी हां। दोनों पक्षों द्वारा एक आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(घ) अंग्रेजी।

अमरीका से कम्प्यूटर की खरीद

1176. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 फरवरी 1986 के हिन्दी दैनिक "हिन्दुस्तान" के प्रथम पृष्ठ पर "पचास करोड़ डालर के कम्प्यूटर सौदे" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, इस संबंध में अमरीका द्वारा किन शर्तों की पेशकश की गई है तथा इस सौदे को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा और कम्प्यूटरों को कब तक हमारे देश में पहुंचा दिया जायेगा ; और

(ख) क्या इस कम्प्यूटर से हिन्दी में कार्य करना संभव होगा या हिन्दी में काम करने के लिए व्यवस्था की जायेगी ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) जी हां। भारत सरकार ने देश में मुख्य ढांचे का (मेनफ्रेम) कम्प्यूटर प्रणालियों के विनिर्माण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की कन्ट्रोल डेटा इण्डोएशिया कम्पनी (सी०डी०सी०) के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। प्रौद्योगिकी के अन्तरण की कुल लागत, जिसमें कम्प्यूटर प्रणालियों का आरम्भिक आयात शामिल है लगभग 2 करोड़ 90 लाख डालर है न कि 50 करोड़ डालर, जैसाकि ऊपर उल्लिखित समाचार में बताया गया है। सी०डी०सी० ने सहयोग के करार के अन्तर्गत साइबर 810 तथा 830 नामक अपनी दो कम्प्यूटर प्रणालियों की पेशकश की है। इस सहयोग की शर्तें उस समझौता-पत्र के अनुसार हैं जिसे दोनों देशों ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। प्रौद्योगिकी के इस अन्तरण से चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भिक 1-1½ वर्षों में वास्तविक प्रयोगकर्ताओं के लिए कुछ कम्प्यूटरों का आयात किया जाएगा।

(ख) नवम्बर, 1984 में घोषित कम्प्यूटर नीति के अनुसार, इन कम्प्यूटरों में देवनागरी इनपुट-आउटपुट की सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे।

हिन्दी का वार्षिक प्रगामी कार्यक्रम

1177. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले 17 वर्षों के दौरान एक बार भी किसी केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग/उपक्रम द्वारा, यहां तक की राजभाषा विभाग द्वारा भी हिन्दी का वार्षिक प्रगामी कार्यक्रम पूरा नहीं किया गया है ; तथा प्रधानमंत्री ने 19 सितम्बर, 1985 को विज्ञान भवन में सभी संबंधित विभागों से 1985-86 के वार्षिक कार्यक्रम को पूरा करने का आग्रह किया था ;

(ख) मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 1985 के बाद से इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाए गये है ;

(ग) क्या यह सच है कि संसदीय राजभाषा समिति में न तो स्वतंत्र रूप से कोई सचिव है और न ही पर्याप्त कर्मचारी हैं जिससे कि वह सभी संबंधित कार्य कर सकें ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृहमंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) राजभाषा विभाग एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए आम लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। मंत्रालय, अधिकारी और उपक्रम अपने प्रभार के अन्तर्गत इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन कभी-कभी व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण वे इन लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

(ग) और (घ) संसदीय राजभाषा समिति में पूर्णकालिक सचिव नियुक्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

अन्य देशों के अधिकारियों की नियुक्ति

1178. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मादक द्रव्यों की देखभाल करने के लिए कुछ देशों ने भारत में अपनी एजेंसियां खोलने तथा अधिकारी नियुक्त करने के प्रस्ताव भेजे है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं तथा उक्त प्रस्तावों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) यूनाइटेड किंगडम सरकार ने ब्रिटिश हाई कमीशन, नई दिल्ली तथा उप हाई कमीशन बम्बई में एक-एक औषध सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव किया है। उक्त प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

संयुक्त राज्य औषध प्रवर्तन अधिकरण के दो अधिकारी इस समय संयुक्त राज्य अमरीका के राजदूतावास, नई दिल्ली में तैनात हैं।

Switching over to Nuclear Power Stations

1179. DR. SHYAM SUNDAR MOHAPATRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state whether India is switching over to nuclear power stations; if so, whether any negotiation with any foreign organisation is afoot?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND IN THE DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI SHIVRAJ PATIL) In future, nuclear power stations are expected to make greater contribution to electric power generation in the counry. W presently have offers from Soviet Union, France and other countries.

Talks of Minister of External Affairs with the U.S. Government

1180. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) what issues were discussed with the US Government during the recent visit of the Minister for External Affairs to the US and what is the outcome thereof; and

(b) whether these talks have resulted in a better understanding of India's position by the US in the matter of continued arming of Pakistan by it with most modern and sophisticated warheads thereby endangering the peace in the sub-continent?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) During his visit to USA in February, 1986 in connection with the Sixth session of the Indo-US Joint Commission, Minister for External Affairs discussed various bilateral, regional and international issues with senior representatives of the US Government.

(b) Government of India's concern at the continuing supply of sophisticated arms to Pakistan was reiterated to the US side in order to make them understand the undesirable consequences of such supplies.